during the eighth Five Year Plan and the entire Plan allocation for this scheme, could be utilised.

Allocation of Government Accommodation

923. DR. YELAMANCHILI SHIVAJI : Will the Mnister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the number of residential Units type-wise available with Government for allotment to Government employees in Delhi/New Delhi as on 1st April, 1992;

(b) what is the shortfall typewise; and

(c) what is the required minimum service put in by Government employee to get the allotment of Government accommodation in each type ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) and (b) Statement is attached. (*see* below)

(c) No minimum service is fixed for government employee to get the allotment of General Pool accommodation subject to availability of vacant quarters and demand from eligible employees the period varies. The position of waiting period of General Pool accommodation as on now is as below :

T. I	14 years
T. II	29 years
T. III	31 years
T. IV	29 years

As regards T. V and higher categories of accommodation the allotment is not made on the basis of length of service. The entitlement is fixed on the basis of the pay of the officer as on 1-10-91 and priority is decided on the basis of higher pay.

Statement

Statement showing the number of residential units available in the General Pool and shortage as on 1-4-92 in Delhi/New Delhi

Type	Availability	Shortage* (approx.)
I	17,841	2,150
II	23,801	8,700
III	17,121	14,700
IV	4675	2,940
IV-Special	378	200
V	1,840	837
VI	537	236
VII	113	177
VIII	108	127

*The figures are based on the limited applications called for the current allotment year (i.e. 1992-93).

देश में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या

924. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है तथा उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है,

(ख) उन्हें उपयुक्त आवास प्रदान करने तथा गंदी बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं के प्रावधान सम्बन्धी नियम क्या-क्या हैं, और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य क्या-क्या हैं और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) भारत की

स्लम जनसंख्या 1991 में 466·24 लाख आंकी गई थी । उसके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं । (नीचे देखिए)

(ख) "शहरी विकास" राज्य का विषय है और स्लम उन्मूलन तथा सुधार की विशिष्ट योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार बनाई और कार्यान्वित की जाती हैं । सरकार की वर्तमान नीति उनके उन्मूलन तथा पुनर्स्थापना की अपेक्षा स्लमों के पर्यावरणीय सुधार पर बल देती है । शहरी स्लमों के पर्यावरणीय सुधार राज्य क्षेत्र की योजना के अंतर्गत शहरी स्लमों में बरसाती पानी की निकासी, जल आपूर्ति, मल-निर्यास, सामुदायिक शौचालय और स्नानघर, गलियों को चौड़ा करना तथा खडंजे बिछाना और पथ-प्रकाश जैसी मूल सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ।

(ग) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए लाभान्वयन के वास्तविक लक्ष्य क्रमशः 15,39,521 और 12,95,584 स्लम निवासी थे । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार वर्ष 1990-91 और 1991-92 की उपलब्धि क्रमशः 19,35,907 और 16,24,492 स्लम निवासी थे ।

विवरण

(आंकड़े लाखों में)

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमानित स्लम जनसंख्या 1991
1	2	3
1	आन्ध्र प्रदेश	42.93
2	अरुणाचल प्रदेश	00.21
3	आसाम	04.14
4	बिहार	35.34
5	गोवा	00.83
6	गुजरात	25.67
7	हरियाणा	06.83
8	हिमाचल प्रदेश	00.94
9	जम्मू व कश्मीर	06.09
10	कर्नाटक	23.63
11	केरल	13.59
12	मध्य प्रदेश	27.67
13	महाराष्ट्र	66.66
14	मणिपुर	00.85
15	मेघालय	00.75
16	मिजोरम	00.63
17	नागालैण्ड	00.44
18	उड़ीसा	08.41
19	पंजाब	13.17
20	राजस्थान	19.60

1	2	3
21	सिक्किम	00.05
22	तमिलनाडु	35.60
23	त्रिपुरा	00.73
24	उत्तर प्रदेश	58.47
25	पश्चिम बंगाल	46.15
26	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	00.15
27	चण्डीगढ़	01.15
28	दादरा और नागर हवेली	00.02
29	दमन और द्वीव	00.09
30	दिल्ली	24.19
31	लक्ष्य द्वीप	00.05
32	पांडिचेरी	01.23
	योग :	466.24

उत्तर प्रदेश में निम्न आय वर्ग के लिए मकानों का निर्माण

925. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में निम्न आय वर्ग हेतु मकानों के निर्माण का लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में निम्न आय वर्ग को आवंटित किए गए मकानों की जिलावार संख्या कितनी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) से (ग) आवास राज्य का विषय है और आवास के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कोई स्कीम नहीं है । 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत, पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में निम्न आय समूह आवास के लिए उपलब्धि इस प्रकार बताई गई थी :

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
90-91	7500	8251
91-92	7500	8226

जिलेवार आवंटित किए गए मकानों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

Phenominal increase in Traffic in Delhi

926. SHRI H. HANUMANTHAPPA : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the phenominal increase of Traffic in Delhi; and

(b) if so, what detailed steps are proposed to be taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) and (b) It is a fact that there has been a tremendous increase in the vehicular traffic in Delhi. To meet this situation, Delhi Administration got a techno-economic feasibility study conducted by M/s Rail India Technical & Economic Services Ltd. (RITES). The feasibility report recommended the introduction of a multimodal rapid transport system over a total route length of 184.5 Kms. The total estimated cost of the project is Rs. 7500 crores at current prices.